University Grants Commission, New Delhi Recognized Journal No. 41311
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X

भारत में उच्च शिक्षा की मुख्य कमजोरियाँः एक अध्ययन

Dr. Rupesh Kumar

M.A, Ph.D (History), B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

सार संक्षेप

विश्व गुरू का दर्जा प्राप्त भारत में शिक्षा का इतिहास अति प्राचीन है। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा के प्रमुख केद्र काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशीला, वतलमी, ओदंतपुरी, जगदल, नदिया, मिथिला, प्रयाग आदि थे। इस शिक्षा केद्रों की ख्याति इतनी अधिक थी कि दूर–दूर से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। भारत में कई शिक्षा केंद्र की वैश्विक पहचान थी जिसमें दूसरे देशों के विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस असंख्य विद्यार्थियों में हेनसांग का नाम सबसे प्रमुख है। उन्होंने अपनी कई पुस्तकों में भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। हजारों वर्षो तक भारत के ये शिक्षा के केन्द्र अपनी चमक बिखेरती रही। विदेशी आक्रमणकारियों एंव तत्कालीन शासकों की उदासीनता के कारण धीरे–धीरे शिक्षा के ये केन्द्र धाराशायी होते चले गये। बौद्धकाल तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था अपने उच्चतम मुकाम पर पहुॅच चुकी थी। शनैः शनैः विश्व गुरू का दर्जा प्राप्त भारत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया परिणामस्वरूप 1916 तक भारत में केवल पॉच विश्वविद्यालय ही अस्तित्व में थे। खासकर उच्च शिक्षा के मामले में हम इतने पिछड गये हैं कि द टाइम्स विश्व यूनिवर्सिटीज रैंकिज (2013) के अनुसार अमरीका का कैलफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी चोटी पर हैं जबकि भारत के पंजाब विश्वविद्यालय का स्थान विश्व में 226वॉ है। यहॉ तक कि भारत के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में भी शामिल नही हैं।

भारत में उच्च शिक्षा की अनेक कमजोरियॉ हैं। लचर शिक्षा के लिए सरकारी नीतियॉ काफी जिम्मेवार हैं। आज भारत में एकाध विश्वविद्यालयों को छोड़कर कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नही हैं जहॉ पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों। उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम यानि केवल 11 फीसदी है। अमरीका में यह अनुपात 83 फीसदी है। समय रहते उच्च शिक्षा में आयी गिरावट पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा अन्यथा हमारी शिक्षा व्यवस्था पिछड़ती चली जायेगी। परिणामतः हम विकासशील देश ही बनकर रह जायेंगे।

मुख्य शब्दः शिक्षा, शिक्षक, शिक्षानीति, आयोग, गिरावट आदि

अवधारणात्मक व्याख्याः भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बडा उच्च शिक्षा तंत्र है। स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में काफी प्रगति हुई हैं। भारत में सार्वजनिक और निजी देनों विश्वविद्यालय है जिनमें कई भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समर्पित है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय भी मौजूद हैं जो विभिन्न निकायों और समितियों द्वारा समर्थित है। शीर्ष दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालयों के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों में से अधिकांश भारत में स्थित है। भारत में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें चालीस केंद्रीय विश्वविद्यालय मानव संसाध्न विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं एवं कृषि मंत्रालय जहाणरानी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक एक कंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं

जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना हैं। यह भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालयों की संख्या में वर्ष 1950 में 20 से 2014 में 677 तक 34 गुणा वृद्धि हुई है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयें के अतिरिक्त 318 राज्य विश्वविद्यालय 129 समविश्वविद्यालय, 51 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ जिसमें IIT 16, NIIT 30 और IISER 5 शामिल है। 1950 में जहॉ देशभर में 500 कॉलेज थे वही 2014 में इनकी संख्या बढकर 37204 हो गई है जो 74 गुणा है। यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद से उच्च शिक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है किंतु आज भी हम उच्च शिक्षा के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफी पिछडे हुए हैं। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर जीडीपी का 1.5 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा पर जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौपी थी वह काफी चिंताजनक थी। उच्च शिक्षा से जुडे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनपर अमल करना आवश्यक है।

स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा में सुधार हुतु कोठारी आयोग, प्रो0 यशपाल कमिटी आदि का गठन किया गया रिपोर्ट भी आयीं। 1986 ई में रोजगारोन्मुखी नयी शिक्षा नीति भी लायी गयी पर आज भी हम एक अदद मूल्यपरक शिक्षा नीति की बाट जो रहे हैं। नैसकॉम और मैकिन्से के ताजा शोध के मुताबिक मानविकी में 10 में एक और अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त 4 में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं। नैक का शोध बताता है कि इस देश के 90 फीसदी कॉलोजों एंव 70% विश्वविद्यालयों का स्तर बेहद कमजोर है। इंफोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति का मानना है कि शिक्षा प्रणाली की बदौलत ही अमरीका ने एभी कंडक्टर, सूचना तकनीकी और बायो टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है इस सबसे पीछे वहॉ के विश्वविद्यालयों में किए गए शोध का बहुत बडा हाथ है। दुनिया भर में विज्ञान और अभियंत्रिकी के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमरीका में होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत से सिर्फ 3 फीसदी शोध पत्र ही प्रकाशित होते हैं। कुल मिला जुलाकर कहा जाये तो भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं अपितु चिंताजनक कही जा सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग

वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के समक्ष अनेक चुनौतियॉ थी जिसमें निम्न साक्षरता दर भी एक बडी समस्या थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति किये बगैर राष्ट्र का विकास असंभव था। तत्कालीन भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए अनेक आयोगों का गठन किया गया जिसमें कुछ प्रमुख निम्न हैं

1. राधाकृष्णन आयोग (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग)
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग
3. कोठारी शिक्षा आयोग
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति
5. नवीन शिक्षा नीति आदि

उपरोक्त आयोगों में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948–49 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तत्कालीन सरकार द्वारा राधाकृष्णन आयोग की अनेक सिफारिशों को मान लिया गया परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्र्याप्त सुधार हुआ। पंजाब, गौहारी, पूना, सड़की, कश्मीर, बडौदा, कर्नाटक, गुजरात, महिला विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बिहार, श्रीवेकंश्वेर, यादवपुर, वल्लभ भाई, कुरूक्षेत्र, गोरखपुर, विक्रम, संस्कृत वि0 विद्यालय आदि अनेक नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन किया गया जो देशभर में मौजूद विश्वविद्यालयों को गाइड लाइन प्रदान करता है।

उच्च शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। प्रो हवाइडेड ने

विश्वविद्यालयों का राष्ट्र निर्माण में योगदान के संदर्भ में लिखा है ''विश्वविद्यालयों ने हमारी सभ्यता के बौद्धिक मार्गदर्शकों प्रशिक्षित किया है। यहीं से विधिज्ञ राजनीतिविद, चिकित्सक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक एंव साहित्यसेवी निकलते हैं। विश्वविद्यालय की महत्ता को देखते हुए राधाकृष्णन आयोग ने इन्हें किसी राष्ट्र के आंतरिक जीवन के पुण्यस्थान की संज्ञा दी है। उच्च शिक्षा में गुणवता और स्वायत्ता महत्वपूर्ण पहलू है। गुणवता के बिना शिक्षा अपने उद्येश्यों को प्राप्त कर पाएगी यह कहना शायद बहुत बडी भूल होगी। दुर्भाग्यवश देश में उच्च शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस संदर्भ में कई ऐसे अहम प्रश्न हैं जिनका निदान निकालना नितांत आवश्यक है। सामान्यतः उच्च शिक्षा में तीन प्रमुख कार्य करने होते हैं शिक्षण, शोध तथा अकादमिक प्रशासन। हम इन तीनों मामले में पिछडे हुए है। विश्वविद्यालयों में न शिक्षण कार्य सही ढंग से हो रहे हैं न ही शोधकार्य ही। अकादमिक प्रशासन मामले में भी दिशा में निम्न कमियॉ दृष्टिगोचर होती है।

1. स्कूलों की तुलना में कॉलेजों में पढने वाले छात्रों का अनुपात काफी निम्न हैं। मसलन स्कूल में पढाई करने वाले नौ छात्रों में से एक ही कॉलेज तक पहुॅच पाता है।
2. भारतीय विश्वविद्यालय औसतन हर पांच वें से दसवें वर्ष में अपना पाठ्यक्रम बदलते है लकिन तब भी ये मूल उद्येश्य को पूरा करने में विफल रहते है।
3. अच्छे शिक्षण संस्थानों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेजों मे प्रवेश पाने के लिए कट ऑफ प्रतिशत असमान्य हद तक बढ़ जाती है।
4. शोध के मामले में भारतीय विश्वविद्यालय काफी पिछडे हुए है।
5. भारतीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी का आलम यह है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 फीसदी शिक्षकों की कमी है। उच्च विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में रिक्तियों की संख्या अधिक है। उदाहरण के लिए बिहार के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्याल, पटना विश्वविद्यालय में सृजित पद और कार्यरत शिक्षकों की संख्या पर गौर करने से हमें इस बात का अहसास हो जाता है कि बिहार में उच्च शिक्षा मरणासन्न अवस्था में पहुॅच चुकी है। इसके लिए हम निम्न आकडे पर गौर कर सकते है।

पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों के सृजित पद और कार्यरत शिक्षक

विभाग/कॉलेज	सृजित पद	कार्यरत शिक्षक
स्नातकोत्तर विभाग	296	110
सइंस कॉलेज	112	28
पटना कॉलेज	75	29
बी एन कॉलेज	153	45
मगध महिला कॉलेज	95	28
पटना बीमेंस कॉलेज	51	25
पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज	12	02
पटना ट्रेनिंग कॉलेज	10	02
पटना लॉ कॉलेज	29	05
कॉलेज आफ ऑर्ट एंड क्राफ्ट	12	11
वाणिज्य	18	9

उपरोक्त ऑकडे बिहार के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के हैं। अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति तो और भी खराब है। यही हाल देश के लगभग अन्य सभी विश्वविद्यालयों का है। कुछेक अपवादों को छोड़कर

6. विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने के संस्थान बनकर रह गये हैं। छात्रों को ज्ञान अर्जित करने की अपेक्षा डिग्री ग्रहण करने में अधिक रूचि है।
7. विश्वविद्यालयों में शिक्षा का निम्न स्तर छात्रों को आकर्षित नही ंकर पाता है।
8. प्रयोगशाला में सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गयी है। अधिकांश महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त है।
9. विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र न रहकर राजनीति का अखाड़ा अधिक प्रतीत होते है।
10. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की निम्नमित बहाली नहीं होने के कारण मेधावी छात्र शिक्षण कार्य करने की अपेक्षा अन्य रोजगार में अधिक रूचि दर्शाते है।
11. शिक्षकों की योग्यता की संदेह के घेरे में रहती है।
12. उच्च शिक्षक पर सरकार की उदासीनता भी गिरती शिक्षा, व्यवस्था का एक बड़ा कारण है।

राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के उद्येश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा का उद्येश्य नवीन विचारधाराओं को जन्म देना तथा नवीन मान्यताओं और पुरानी मर्यादाओं के माध्य समन्वय स्थापित कर विकास की ओर बढते रहने की प्रेरणा देना है। इसे महज दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में देश में उच्च शिक्षा संक्रमण काल से गुजर रही है। जहॉ एक ओर अमेरिका, चीन आदि देशों में उच्च शिक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता है एवं वार्षिक बजट की एक बडी राशि इस पर खर्च की जाती है वही दूसरी ओर भारत में लगभग 1.5 प्रतिशत ही कुल जीडीपी का उच्च शिक्षा पर वहन किया जाता है। देश की युवा पीढी का ध्यान उच्च शिक्षा ग्रहण करने से भटकाकर उनका ध्यान मंदिर–मस्जिद की ओर मोड़ दिया जाता है। आज देश में जो बड़े–बडे मुद्दे है वह यह है कि मंदिर कहॉ बनना चाहिए, आरक्षण पर बड़े–बड़े डिवेट कराये जाते हैं। सरकार का ध्यान और न ही देश की जनता का ध्यान इस ओर जाता है कि जब तक हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था मजबूत नही होगी हम तरक्की की राह पर आगे बढ ही नही सकते। मंदिर–मस्जिद, मंडल–कमंडल में उलझा देश का युवा पीढी खुद को छला एंव ठगा महसूस करता है। शायद यही उसकी नियति बना दी गई है।

निष्कर्षः अति समृद्ध अतीत होने के बावजूद भारत में उच्च शिक्षा दम तोडती नजर आ रही है। कागज पे ऑकडे तो आकर्षक लगते है किंतु वास्तविकता इससे काफी भिन्न है। सवा सौ करोड की आवादी वाले इस देश में उच्च शिक्षा हमेशा बदलाव के दौड़ से गुजरती रही है। लगभग प्रत्येक दस साल पर विश्वविद्यालयों के सिलेबस में छेडछाड कर दिया जाता है। निःसंदेह इससे गुणवता पूर्ण शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। प्रचुर मात्रा में विश्वविद्यालयों का अभाव, शिक्षकों का अभाव, शिक्षण संस्थानों में उपस्कर का अभाव, छात्रों की उपस्थिति का निम्न ऑकडा आदि अनेक ऐसी कमियॉ जिससे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था जूझती नजर आती है। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, गुणवता पूर्ण शिक्षा का अभाव, शोध कार्य के लिए संसाधन का अभाव, ज्ञानपरक शिक्षा का अभाव, आदि ऐसे अनेक कार्य है जिससे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आयी है। अतः वक्त रहते इन कमियों को दूर कर उच्च शिक्षा को दुरूस्त करने की आवश्यकता है। अन्यथा इसके गंभीर परिणाम राष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है।

संदर्भः

1. http; //hi.m. Wikipedia.org
2. राधाकृष्णन आयोग का रिपोर्ट
3. शर्मा सुभाष, भारत में शिक्षा व्यवस्था, अवधारणाएँ समस्याएँ एवं संभावनाएँ (2005), वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृ0 सं0– 23
4. अध्ययन सामग्री : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा।
5. अध्ययन सामग्री : नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना।
6. अध्ययन सामग्री : इग्नू, नई दिल्ली
7. शर्मा, नागेश्वर : बिहार के ढहते विश्वविद्यालय पृ0 सं0 – 29
8. दैनिक हिन्दुस्तान, पटना संस्करण, दिनांक– 12 अप्रैल 2018, पृ0 सं0 – 13